भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *180

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"बैटरी डिकपलिंग संबंधी नीति"

***180. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:**
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, बैटरी डिकपलिंग के संबंध में एक ठोस नीति बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों की सततता को बढ़ाने के संदर्भ में बैटरी डिकपलिंग से जुड़े संभावित फायदों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है या शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विभिन्न ईवी मॉडलों, बैटरी केमिस्ट्री और चार्जिंग अवसंरचना के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए बैटरी डिकपलिंग में मानकीकरण और अंत: क्रियाशीलता के मुद्दे का समाधान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैटरी डि-कपलिंग के क्षेत्र में कोई प्रायोगिक परियोजनाएं अथवा अनुसंधान और विकास कार्यकलाप शुरू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

<u>विवरण</u>

"बैटरी डि-कपलिंग संबंधी नीति" के संबंध में लोक सभा में 01.08.2023 को उत्तर के लिए नियत श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल और डॉ. सुजय विखे पाटील के तारांकित प्रश्न संख्या 180* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): नीति आयोग से प्राप्त सूचनानुसार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जून-2021 में प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। बैटरी पैक और कनेक्टर की भरपूर उपलब्धता के कारण उनका अध्ययन करने और देश के लिए साझा समाधान प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित एक तकनीकी निर्णायक मंडल ने 40 हितधारकों से जानकारी एकत्रित की जिनमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, कनेक्टर के विनिर्माता और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला आदि थे।

सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों की सततता के संवर्धन के संभावित लाभों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए हैं और रिपोर्टें तैयार की हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के प्रभावों को समझना और ऐसी नीतियां तैयार करना है जिनसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में सहायता मिले और इसमें तेज़ी लाई जा सके। अध्ययनों के निष्कर्ष निम्नांकित लिंक पर हैं-

https://www.niti.gov.in/e-mobility-national-mission-transformative-mobility-andbattery-storage

https://e-amrit.niti.gov.in/reports-and-articles

(ग): नीति आयोग से प्राप्त सूचनानुसार, बैटरी-स्वैपिंग नीति का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए वर्ष 2022 में जारी किया गया था और फीडबैक को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

(घ): जी, नहीं।

***